राजस्थान में हर साल मानसून शुरु होने पर गरीब किसानों को उनके खेत काश्त करने के लिए शार्ट टर्म लोन के रूप में तकावी बांटी जाती है। यह तकावी शार्ट टर्म (लोन) सूखे के बाद के साल में विशेष रुप से बहुत बड़ी मात्रा में बांटी जाती थी। यह साल सूखे के बाद का है लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान सरकार ने किसानों को कोई तकावी नहीं दी। इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से गरीब किसान, विशेषकर हरिजन तथा आदिवासी किसान अपने खेत जोते बिना रह गये। इससे गरीब किसानों का अहित तो हुआ ही लेकिन अनाज का उत्पादन भी गिरेगा। बहुत से हरिजन तथा आदिवासी किसानों ने अपने खेत काश्त करने के लिए दूसरी जाति के सम्पन्न किसानों को दे दिए हैं तथा राजस्थान सरकार की इस कार्यवाही के कारण उनको अपने ही खेतों में मजदूर बनना पड़ा है।

(vii) POLICY OF RAILWAYS TO AUCTION RAILWAY PLOTS

SHRI NARAYAN CHOUBEY (Midnapore): Sir, the Railway Ministry have adopted a new policy to auction railway plots to give to various persons for the purpose of business. Previously, the plots were allotted by a Committee, and such persons who used to secure plots used to pay rent to the Railways on a monthly basis Many common persons including old ex-Railwaymen, sons of Railwaymen and poor shop-keepers and hawkers could secure some plots by that policy. The new policy will only help the rich to secure and monopolize railway plots. The Minister of Railways must immediately intervene, so that the new policy is scrapped. Otherwise, there will be serious unrest in the railway settlements arising out of serious discontent flowing from the new pro-rich policy of the Railway Ministry.

(viii) IMMEDIATE DESPATCH OF FOOD-GRANTS TO FAIMINE AFFECTED PARTS OF RAJASTHAN

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वक्तव्य देना चाहता हूं --

"राजस्थान के दक्षिणी भाग के आदिवासी क्षेत्रों में वर्षा नदारद। अकाल काम बन्द, पुराने अकाल में नये अकाल का प्रवेश। नाज की कमी के कारण अनाजों के भाव गगन-चुम्बी शक्कर के भाव 10-12 रुपये प्रतिकिलो, मजदूरों को दो-दो माह से भुगतान नगण्य, भारतीय कृषि निगम से कोई नाज नहीं भेजे जाने के आकाल की भंयकर स्थिति भुखमरी में परिवर्तित हो रही है। अतः केन्द्रीय सरकार नाज की व्यवस्था कर मजदूरों के लिये राज्य सरकार को निर्देश दिलायें।

(ix) PURCHASE OF SURPLUS PADDY IN PUNJAB

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): There are no arrangements to buy the surplus paddy in Punjab. The FCI which is to take the responsibility is not deciding even to purchase 25 per cent of the surplus stocks in the State. The State Government is not in a position to purchase all the surpluses. In the ensuing season it is expected that there will be 45 lakh tonnes of paddy to be marketed in the State. The State government is unprepared to purchase because it does not have increased godown capacity and milling capacity on par with the increase in production of paddy. In the next three years the marketable surplus will be 70 lakh tonnes.

Neither the state government not the Central Government are having future projections of production of pady and storing and other arrangements to be made to meet the situation. This is creating difficulty every year to the paddy producers who are

[Shri P. Rajgopal Naidu]

facing problems regarding selling the surplus stocks of paddy with them.

Now the Central Government and the Punjab government should come to an understanding between them- of paddy in the state. If it is not done, selves in purchasing all the surpluses soon, there will be frustration among the agriculturists and there will be a set-back to the increased production of paddy.

Meanwhile the government should explore the posibilities of exporting rise, especially finer varieties of rice in larger quantities so as to help the agriculturists.

(x) NEED TO PROTECT THE SAMADHI OF LATE RAJA MAHENDRA PRATAP, A FREEDOM FIGHTER

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 277 के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

''देश के महान क्रांतिकारी देशभक्त व त्यागी नेता स्व० राजा महेन्द्र प्रताप जिन्होंने अपनी रियासत के एक भाग का दान कर के प्रेम महाविद्यालय, जो दस्तकारी के साथ पढ़ाई कराने वाला प्रथम विद्यालय था, की स्थापना की । देश की स्वतन्त्रता के लिये लड़ने वाले क्रांतिकारी नेता राजा साहब को अंग्रेजी सरकार ने विद्रोही घोषित करके 32 वर्ष तक अपने देश में नहीं जाने दिया । दान के बाद बची हुई उन की समस्त रियासत को जब्त कर लिया और वह जब्त की हुई रियासत देश के स्वतन्त्र हो जाने के बाद भी वापस नहीं मिली । विदेशों में रह कर 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के समय देश की स्वतन्त्र सरकार की काबुल में स्थापना की । अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की । उस सरकार को अन्य कई देशों की सरकारों ने मान्यता दी । स्वर्गवासी होने से पूर्व अपने परिवार के स्थान पर प्रेम महाविद्यालय के लिये बची हुई सम्पत्ति की वसीयत की ।

उन की इच्छा के अनुसार यमुना के किनारे प्रेम महाविद्यालय के सामने राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को यमुना की बालू में समाविष्ट किया गया । प्रदेश के प्रधान मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने उन का स्मारक बनाने का आश्वासन दिया था ।

केन्द्रीय सरकार के आवास मंत्री ने 8 जुलाई, 1980 को अतारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया है कि सरकार के सम्मुख राजा साहब के स्मारक का विषय विचाराधीन नहीं है ।

देश के महान देशभक्त, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, असाधारण त्यागी नेता राजा महेन्द्र प्रताप, जिन्होंने समस्त देशों की एक सरकार संसार संघ बनाने की विचारधारा रखी, सब धर्मों के विचारों को लेकर प्रेम धर्म की स्थापना की, जिन को देश की तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जहां स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्रपत्र व पेंशन दे कर सम्मानित करके प्रशंसनीय कार्य किया था वहां सर्वप्रथम ताम्रपत्र राजा महेन्द्र प्रताप को देकर और उन्हीं के सभापतित्व में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करके विशेष प्रशंसनीय कार्य किया था । वे ही देश की स्वतंत्रता सेनानियों की समिति के सभापति थे । आज यमुना के किनारे बालू में बनी उनकी समाधि यमुना की बाढ़ के कारण खतरे की स्थिति में पहुंच गई है । कभी भी उनकी समाधि उनके पार्थिव शरीर के साथ यमुना में बह सकती है । यदि ऐसा